भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 522 का उत्तर

नई रेल लाइनों का निर्माण

522. श्रीमती प्रमिला बिसाईः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नई रेल लाइनों हेतु आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य में नई रेल लाइनों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है; और

(ग) ओडिशा राज्य के दूरवर्ती क्षेत्रों में बेहतर संपर्क के लिए नई रेल लाइनों के तेजी से निर्माण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क): वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय रेल पर नई लाइनों के लिए बजट परिव्यय 9477.77 करोड़ रुपए है।

(ख): रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन परियोजना - वार किया जाता है, न कि राज्य-वार। ओडिशा पूर्व तट रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आता है। परियोजना-वार धनराशि के आबंटन और व्यय के ब्यौरे भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात www.indianrailways.gov.in>Ministry of Railways>Railway Board>About Indian Railways>Railway Board Directorates>Finance (Budget) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। इस सूची में ओडिशा सहित सभी राज्यों के निर्माण कार्य शामिल हैं।

Sk

(ग): किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालय के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक एक परियोजना से दूसरी परियोजना और एक स्थल से दूसरे स्थल की तुलना में भिन्न-भिन्न होते हैं और परियोजना के समापन समय तथा लागत को प्रभावित करते हैं।

समग्र राष्ट्र के हित में और लागत में वृद्धि हुए बिना परियोजनाएं समय पर पूरी करना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तंर, क्षेत्रीय स्तर एवं बोर्ड स्तर) पर पूरी निगरानी रखी जाती है तथा राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों का समाधान किया जा सके।

परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने हेतु सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने ठेकों में बोनस खंड के रूप में ठेकेदारों के लिए प्रोत्साहन अवधारणा अपनाई है, जिससे परियोजनाओं के निष्पादन में और तेजी आएगी।

*****

Sk